

संख्या-716 / XVIII(II) / 2010-3(24) / 2010

प्रेषक,

एस0के0 मुटू,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,  
कुमाऊं मण्डल,  
नैनीताल।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 2-6-2010

**विषय :-** निदेशालय, समाज कल्याण हल्वानी एवं सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, कुमाऊं सम्भाग, हल्वानी के कार्यालय एवं आवासीय भवनों के निर्माण हेतु भूमि आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-691/सात-33/भू0 अ0/2009-2010, दिनांक-15/02/2010 के संदर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, निदेशालय, समाज कल्याण हल्वानी एवं सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, कुमाऊं सम्भाग, हल्वानी के कार्यालय एवं आवासीय भवनों के निर्माण हेतु ग्राम मानपुर पूरब, तहसील हल्वानी, जिला नैनीताल में 1.97 एकड़ भूमि समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड एवं 1.97 एकड़ भूमि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड को जो वर्तमान में उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की है एवं श्रेणी 5 (3) ड में दर्ज है, को आपके द्वारा की गयी संस्तुति एवं वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-260/वित्त अनुभाग-3/2002 दिनांक 15/02/2002 के दृष्टिगत निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निशुल्क हस्तांतरण की कार्योत्तर सहर्ष प्रदान करते हैं :

- 1- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- 2- जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तांतरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।
- 3- हस्तांतरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

-2-

- 4- यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तांतरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।
- 5- जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तांतरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना हस्तांतरित नहीं की जायेगी।
- 6- जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने की अधिकार होगा।
- 7- प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अंतर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

भविष्य में भूमि हस्तांतरण से संबंधित प्रस्ताव, नियमानुसार शासन के अनुमोदनोपरांत ही निर्गत किया जाये।

भवदीय,

(एस० के० मुद्दू)  
प्रमुख सचिव

पृ०प०संख्या- 716 /समदिनांकित/2010

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- जिलाधिकारी, नैनीताल।
- 5- निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय।
- 6- प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)  
अनु सचिव